

कांडा जमाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

अंक-34	मासिक	मई, 2024	सहयोग राशि 40 रुपये		
इस बार			अवतारी पुरुष के गंदे बोल		
पाठकीय अभियान अमरेन्द्र यादव / रामलखन यादव 3/4 राजनीतिक संग्राम में प्रतिपक्ष देश बचाने और देश बनाने का चुनाव- तेजस्वी प्रसाद यादव 05 उनकी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए हैं- प्रियंका गांधी 07 भाजपा आदिवासियोंको कुचलना चाहती है- कल्पना मुर्मू सोरेन 15 राजनीति की साम्प्रदायिकता संविधान बचाओ मुद्दे की हकीकत क्या है- एस.एन साहू 16 मोदी के भारत में न्यूरेमबर्ग की गूंज- हर्ष मंदर 18 पठन-पाठन 'हंस' का एक और दलित विशेषांक- डॉ. मुसाफिर बैठा 24 श्रद्धांजलि चौथीराम यादव : वंचितों के व्याख्याता का महाप्रयाण- अर्पणा 26 ..वे सच को बोल सकने का सम्बल थे- कमलेश वर्मा 29 ...जो अपने समय से मुठभेड़ करता चला गया- मनीष शर्मा 30 माटी के कवि सुरजीत पातर- जय प्रकाश पांडेय 31 पार्टी गतिविधियाँ सारण चुनाव अभियान की आंखों देखी- प्रियंका रंजन 35 ...प्रियांशु : आपकी प्रतिबद्धता के हम कायल हैं- डॉ. दिनेश पाल 36 जिताइए उन्हें जो आपके सुख-दुःख में शामिल हों- रोहिणी आचार्य 38 कवि का पन्ना / सुमन्त 40	एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी नागरिक समाज या उनके नेताओं से जिस तरह की भाषा बरतने की अपेक्षा की जाती हैं, भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन सब को ध्वस्त करते हुए साम्प्रदायिक ध्वीकरण करने पर आमादा हैं। अपने चुनावी भाषणों के जरिये जिस फूहड़, गंदी और साम्प्रदायिक भाषा वे अपने ही देश के एक खास वर्ग के नागरिकों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, वह खुले तौर पर धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गला घोटना है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान जिस तरह से उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, एक्सरे की मशीन से मंगल सूत्र की चोरी, भैंस चोरी, विरोधियों द्वारा नल की टोंटी तक खोल लेने और अब मुजरा तक की जिस फूहड़, गंदी भाषा को अपने लफजों में लाते रहे हैं, वह बतलाता है कि इस चुनाव में अपनी जाती हुई सत्ता को पाने के लिए वह किसी भी हट तक गिर सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाया बतलाना, क्या यह किसी भी सभ्य देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है, लेकिन मोदी इस तरह की भाषा का प्रयोग धड़ल्ले से करते रहे हैं बौग्र इस बात की परवाह किये कि इसका कितना गलत संदेश जाएगा, देश-दुनिया के लोग क्या करेंगे? 	सम्पादक अरुण आनंद सहयोग कवि जी/ डॉ. दिनेश पाल/ साकिब अशरफी जगदानन्द सिंह प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-01 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित राजद समाचार की ईमेल आईडी samacharrjd@gmail.com			

नई-नई फूहड़ गालियां इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी धर्म और मजहब के लिए इससे बुरी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम सब ने आज तक यही जाना है कि 'मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना'। आर.एस.एस के सिद्धांतकार गुरु गोलवलकर हिन्दू धर्म को जिस संकीर्णता के दायरे में ले जाना चाहते थे, जिस इस्लाम, ईसाइयत के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, वर्तमान निजाम प्रकारांतर से उनकी ही परम्परा को दुहरा रहे हैं, लेकिन वे भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद आर.एस.एस का पद नहीं है, यह भारत की उस धर्मनिरपेक्ष परम्परा का पद है जिसमें सम्पूर्ण भारत की आत्मा वास करती है। इस पर आसीन होकर वे न सिर्फ संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी। अगर वे तीसरी बार सत्तासीन हो गए तो यकीनन न हमारा संविधान बचेगा, न हमारी भारतीयता, न मुल्क का जनतंत्र। साम्प्रदायिक आधार पर जिस तरह से भारतीयता की पूरी अवधारणा को नेस्तनाबूद करने पर वह भिड़े हुए हैं, उनकी उस खतरनाक मंशा को पहचानने की जरूरत है, वरना अगर वे आ गये तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा।

यह सुखद है कि लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरण जैसे-जैसे पार कर रहे हैं चार सौ के पार लोकसभा सीट जीतने का नरेन्द्र मोदी का ख्याली पुलाव न सिर्फ धराशायी होता दिख रहा है बल्कि यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इसबार केंद्रीय सत्ता उनके हाथों नहीं आनेवाली। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न सिर्फ देश-विदेश अपितु खुद अपने संघ और भाजपा के लिये भी नासूर बन गए हैं। यह अकारण नहीं कि स्वयं संघ और भाजपा की ओर से भी उनके विकल्पों पर गहरी जोर-आजमाइश होनी शुरू हो चुकी है। भारत में संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने जिस हया के साथ पूरी तरह नष्ट-भ्रष्ट किया है, उसमें इनकम टैक्स, ईडी अग्रणी रहे हैं। इसमें अब एक और नाम चुनाव आयोग का भी शामिल हो गया है। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी नामक संस्था ने बहुत पहले यह खुलासा किया था कि भारत उन 18 देशों में शामिल है, जिनमें चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का संकेतक काफी हद तक नीचे चला गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान में मोदी सरकार के आगे चुनाव आयोग ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। यह चुनाव आयोग ही सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रचार में शामिल राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें। जातीय, साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली भाजपा की हिमायत और विपक्षी दल पर सवाल खड़े करके निर्वाचन आयोग ने अपनी शाख पूरी तरह से गिरा ली है। चुनाव आयोग द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस और भाजपा नेताओं के नफरती भाषणों पर चुप्पी यह बतलाता है कि मोदी ने भारत की संस्थाओं का क्या हाल बनाकर रखा है। पूरे चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री धार्मिकता की विषयी जहर उड़ेलते रहे, लेकिन चुनाव आयोग के कान में जूँ तक न रेंगी। उनके रवैये से प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन से सिर्फ एन.डी.ए. ही नहीं लड़ रहा मीडिया, सी.बी.आई और ईडी के साथ चुनाव आयोग भी उन्हें हर संभव गहरी शिक्षण देने को आमादा है। अब जबकि चुनाव अभियान के महज दो चरण शेष रह गए हैं, चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस अध्यक्षों

को नोटिस जारी किया है कि वे अपने स्टार प्रचारकों को निर्देश जारी करें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कांग्रेस को आगाह किया है कि संविधान और अग्निवीर का सवाल वे अपने कैम्पेन में न उठायें। क्योंकि यह कदम सैन्य प्रशासन में हस्तक्षेप है और संविधान का खतरा दिखलाकर भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। किसी संवैधानिक संस्था का ऐसा पतन भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं देखा गया। यह नरेन्द्र मोदी ही हैं जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए पिछले दिनों निर्वाचन आयोग के गठन में भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म की ताकि वे अपने मन मुताबिक उनका दुरुपयोग करें और आज वह वही कर रहे हैं। मतों का डे-टू-डे पारदर्शी आंकड़ा जारी करने का सवाल हो, या बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी से जुड़ी आशंकाएं- भारत के निर्वाचन आयोग की चुप्पी बतलाती है कि वह पूरी तरह भाजपा की भोपू बन गई है।

प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में जिस तरह से झूठ की खेती की है, उसका भी कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में सम्पत्ति वितरण और मुस्लिम आरक्षण को लेकर सीधा-सीधी झूठ बोला, जिसका उसमें कोई जिक्र भी नहीं था। उसी प्रकार कुछ पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुस्लिम आरक्षण के सन्दर्भ में आदरणीय लालू जी के बयान को तोड़-परोड़ कर अपने ध्वीकरण के एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। उल्लेखनीय है कि लालू जी ने स्पष्ट कर दिया था कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में आरक्षण का आधार जाति होता है, धर्म नहीं होता। मगर मोदी जी ने मुस्लिम आरक्षण, जो सफेद झूठ है, इस चुनाव का मुद्दा बना दिया। हालांकि कि इसमें उनकी निराशा ही झलक रही है क्योंकि इस आधार पर कोई ध्वीकरण होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस चुनाव में भाजपा या कहिये पूरे एन.डी.ए को जिस तरह से मोदीमय बनाने का प्रयास जारी है, उसका ही तार्किक नतीजा है कि मोदी ने खुद को 'दैवीय अवतार' घोषित कर दिया है। कई बयानों में उन्होंने कहा कि उन्हें जो ऊर्जा मिलती है, वह बायोलॉजिकल नहीं, ईश्वरीय है। अभी तक तो कुछ दरबारी ही यह उपाधि देते थे, अब यह सनक खुद उनपर ही सवार हो गया है। इतिहास गवाह है कि सुपर ह्यूमन, अवतारी पुरुष होने का वहम तानाशाह को ही होता है। बिहार में खुद मोदी जी ने और उनकी अगुआई में एन.डी.ए नेताओं ने लालू जी और उनके परिवार पर निजी और ओछे हमलों की सारी हड़ें पर कर दीं। तमाम उक्साओं के बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे राजद और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह संयत होकर इसका मुकाबला किया और अपने मुद्दों पर अडिंग रहे, इसकी मिसाल समकालीन चुनावी इतिहास में शायद ही मिले। अतः समय का तकाजा है कि आप इस फासीवादी, लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाने के लिए सचेष हों ताकि भारतीयता की जो विविधधर्मिता है वह सुरक्षित रहे और भारत की जनता जिस साम्प्रदायिकता, महंगाई और बेराजगारी की चक्की में पिसने को अभिशप्त है, उससे मुक्ति मिले।

अरुण आनंद

